भारी बारिश से कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क

जशपुर,(आरएनएस)। जिले के कुनकुरी एवं बगीचा विकासखण्ड क्षेत्र अंतर्गत रनपुर से बंदरचुआ मार्ग नदी में रविवार को अचानक जल स्त्रोत बढ़ जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। रात भर हुई तेज बारिश के कारण पानी कुनकुरी के गोरिया नाला एवं बगीचा के नंदाटोली नाला में बने पुल के ऊपर से बह रहा है। इससे उक्त मार्ग में आवाजाही थम गया है और कई ग्रामों का संपर्क भी टूट गया है। गोरिया नाला और बगीचा ब्लॉक के नंदाटोली नाला में पानी भरने से दोनों रूटों की बसें भी प्रभावित हुई है। ज्ञात हो की ग्राम गोरिया नाला एवं बगीचा विकास खण्ड क्षेत्र अंतर्गत नंदाटोली नाला इन दिनों हो रहे बारीश के कारण लबाबल भरे हुए हैं। जल स्तर एकाएक बढने के कारण पानी पुल में खतरे के निशान से ऊपर से बह रहा है। एकाएक जल स्तर बढने के कारण उक्त मार्ग से आवाजाही रोक दी गई है। कई ग्रामों का संपर्क भी कुनकुरी से टूट गया है। उक्त नाला में भी जल स्त्रोत बढने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। रात भर हुई बारिश के कारण नदी में उफान आ गया। ग्राम पंचायत रनपुर, जोक बहला, चरेखरा, गोरिया सहित दर्जनों ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामों का संपर्क इस वक्त दोनों तरह की रूटों के अवरूध होने के कारण टूट गया है। इन ग्रामों के दोनों तरफ पानी पुल के उपर से बहने के कारण इस क्षेत्र में निवासरत लोग ना तो बगीचा विकास खण्ड की ओर जा पा रहे हैं और ना तो कुनकुरी विकास खण्ड की ओर जा पा रहे हैं। जिससे यहां निवासरत लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। दोनो ओर से सौकड़ों ग्रामों का मार्ग अवरूध हो जाने के कारण लोग कही भी नहीं जा पा रहे हैं। स्कूली बच्चे भी स्कूल जाने से वंचित हो गए हैं। इस क्षेत्र में कई शासकीय कर्मचारी भी निवासरत हैं जो कुनकुरी एवं बगीचा के कार्यालयों में कार्यरत हैं लेकिन मार्ग अवरूद्ध होने के कारण ये भी अपने दफ्तरों में कार्य के लिए समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे में इनकी भी परेशानी इन दिनों बढ़ी हुई है। वहीं बारिश भी अपने शबाब पर है। कुनकुरी नगर के आसपास के सभी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वही आसपास के सभी नदी-नाले उफान पर हैं। कुनकुरी का डेम पूरी तरह से भर चुका है। पहले बनाए गए बांध को पिछले कुछ वर्षों में आधे बांध पर सीढ़ी बना दिया गय और आधे बांध को खुला छोड़ा गया जिससे की पानी निकासी होता रहता। वहीं बगल में पुराने पानी निकासी के लिए बनाए गये गेट को बंद कर दिया गया। जिससे कि ल÷ातार हो रही बारिश से डेम भर चुका है। और मिट्टी व कीचड़ से बांध के किनारे का हिस्सा भरता जा रहा है। गेट खोला जाता तो डेम की सफाई हो सकती थी और बांध को नुकसान नहीं होता। डेम के निचले हिस्से में स्थित किसानों की जमीने बारिश की वजह से बहुत तालब में तबदील हो चुकी हैं। अब भी मुसलाधार बारिश जारी है।

संसद : मॉब लिंचिंग पर हंगामा, स्पीकर पर फेंके कागज

नई दिल्ली,(आरएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को शून्यकाल के दौरान अशोभनीय व्यवहार करने पर कांग्रेस के छह सदस्यों गौरव गोगोई, अधीर रंजन चौधरी, एम के राघवन, सुष्मिता देव, के सुरेश और रंजीत रंजन को सदन से पांच दिन के लिए निलम्बित कर दिया। वहीं लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग ही नियम तोड़ते हैं तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसी सजा भी ठीक नहीं है, कल इसके विरोध में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है तो हमारे 6 सदस्यों को सस्पेंड कर देना उचित नहीं है।

क्या था घटनाक्रम : लोक सभा में सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और तणमूल कांग्रेस सदस्य आसन के समक्ष आकर गो रक्षा के नाम पर हमलों एवं कथित हत्याओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग करने लगे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने और शून्यकाल में उन्हें अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दिए जाने की बात कही और हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही संचालित की। इसी मुद्दे को लेकर सदन में शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामा करने और कागजात फाड़कर अध्यक्ष के आसन की तरफ फेंके जाने के बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद अपराह्न दो बजे सदन कार्यवाही शुरू होते ही श्रीमती महाजन ने सदस्यों के इस बर्ताव पर गहरा खेद और चिंता जताते हुए कहा कि सदस्यों का यह आचरण सदन की मर्यादा और गरिमा के विपरीत है। इसलिए उन्हें सदन की कार्यवाही से पांच दिन के लिए निलम्बित किया जाता है। महाजन ने कहा कि शून्यकाल के दौरान मल्लिकार्जुन खडगे और कुछ अन्य सदस्य दलितों पर अत्याचार के बारे में चर्चा कराना चाह रहे थे, जिस पर उन्होंने चर्चा कराए जाने का आश्वासन दिया था और संसदीय कार्यमंत्री अनन्त कुमार ने भी इस संबंध में आश्वासन दिया था लेकिन कुछ सदस्यों ने आसन के निकट आकर हंगामा किया। उनसे अपनी सीटों पर जाने का बार बार अनुरोध किया गया लेकिन गोगोई ने आसन के पास मेज से कागज उठाए, उन्हें लहराया और फिर आसन की तरफ फेंक दिया।

सांसदों को दी नसीहत: लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सदन को संचालित करने के नियम सभी ने मिल कर बनाए हैं और सभी सदस्यों का दायित्व है कि वे इन नियमों का पालन करें।

चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाएगा भारत

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। तिब्बत की सीमा तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी से भालुकपोंग होकर तवांग तक 496 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। सुरंग बन जाने से कई घंटे का समय बचेगा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए केंद्रीय रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारी बड़ी-बड़ी सुरंगें तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सीमाई क्षेत्रों में सड़क बनाने वाले संगठन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को तवांग में दो लेन वाले एक सुरंग के निर्माण का काम सौंपा गया है। इस सुरंग के बन जाने से 13,700 फीट ऊंचे सेला दर्रे के इस्तेमाल की जरूरत नहीं रह जाएगी और पहाड़ी यात्रा मार्ग की जगह सीमा तक की दूरी सात किलोमीटर घट जाएगी। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने इस काम के लिए अरुणाचल सरकार से जमीन मांगी है। पूर्वी हिमालयी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों वाले इलाके में इस सुरंग के बन जाने से दूरी तो कम होगी ही, समय भी कई घंटा बचेगा। अभी हाल में बीआरओ से प्रोजेक्ट कमांडर आरएस राव ने पश्चिमी कामेंग की उपायुक्त सोनल स्वरूप से मुलाकात कर उन्हें जमीन की जरूरत के बारे में पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज सौंपे। अभी तिब्बत की सीमा तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी से भालुकपोंग होकर तवांग तक 496 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। सुरंग बन जाने से कई घंटे का समय बचेगा। साथ ही, वाहन तेजी से चल सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, सेला दर्रा का रास्ता तय न करना पड़े इसके लिए तवांग तक 12.37 किलोमीटर की सड़क का काम चल रहा है। 475 मीटर और 1.79 किलोमीटर लंबी सुरंगें इसी परियोजना का हिस्सा हैं। ये सुरंगें 11,000 और 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएंगी। मानसून के बाद इस इलाके में जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। उधर, बांग्लादेश से लगी असम की सामा साल करने क वाद क साथ बीते साल सत्ता में आए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अब इस काम में सेना की मदद मांगी है। राज्य सरकार ने सूबे से संबंधित भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने में सेना के इंजीनियरों को तैनात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। राज्य की 262 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगी है, जिसमें से 208.85 किलोमीटर लंबी सीमा को पहले ही सील किया जा चुका है। बाकी बची सीमा में साढ़े छह किलोमीटर जमीन से जुड़ी है, जिस पर बाड़ लगाई जानी है। बाकी सीमा नदियों से जुड़ी है।

एनएमडीसी कर रही है स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा

दंतेवाड़ा,(आरएनएस)। लौह नगरी बचेली के एनएमडीसी क्षेत्र में जहां एक और बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी और एनएमडीसी में भर्तियांओ में भी रोक लग चुकी है जिसके कारण पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है इन पढ़े-लिखे युवाओं को ठेका श्रमिक के रूप में मजबूरन कार्य करने के लिए भी विवश है परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यह पढ़े-लिखे युवक ठेका श्रमिक के रूप में एनएमडीसी के ऑफिसों में कार्य करने के लिए भी दोनों यूनियनों एवं एनएमडीसी के बड़े अधिकारियों के पास मिन्नतें करते रोजगार की आस में खड़े रहते हैं परंतु वहीं दूसरी और बचेली के स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी करते हुए एनएमडीसी में ठेका श्रमिक के रूप में जनप्रतिनिधियों और ऊंची पहुंच वाले अधिकारियों के खास लोगों की भर्तियां एनएमडीसी कर रही है इसका जीता जागता उदाहरण किरंदुल के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रवेश जोशी का है जो किरंदुल से पार्षद मान देय की मासिक वेतन ले रहे हैं और बचेली एनएमडीसी में ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए यहां से भी मासिक भुगतान हो रहा है बड़ा प्रश्न चिह्न है कि यहां के स्थानीय बेरोजगारों को जहां एनएमडीसी अनदेखा करते हुए किरंदुल से आए पार्षद को यहां ठेका श्रमिक के रूप में कौन से अधिकारी के कहने पर कार्य में लगाया गया है इस बात की दोनों यूनियन के पदाधिकारियों को नहीं थी कोई जानकारी की पार्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस बात पर विवाद होने के बाद दोनों यूनियनों को पता चला था ठेका श्रमिक के लिए बचेली में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा नहीं है यह सोचने का गंभीर विषय है पार्षद अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को छोड़कर बचेली एनएमडीसी में पूरा दिन कार्य कर रहा है फिर किस बात के लिए शासन से पार्षद का मासिक मानदेय ले रहा है उस वार्ड के लोगों की परेशानी का क्या होगा जिस वार्ड की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर ऐसे पार्षद को जिताया है। 1.एनएमडीसी सिविल प्रबंधक चोकसे ने कुछ भी कहने से किया इंकार कहां ऑफिस में आकर मिली है मुझसे। 2. इंटक सचिव रवि मंडल ने कहा है कि मामला गंभीर है इस गंभीर मामले की जांच करने के बाद महाप्रबंधक से बात की जाएगी। 3. एस.के.एम .एस , यूनियन के अध्यक्ष - शंकरराव ने कहा है कि गंभीर मामले पर एनएमडीसी पोजेक्ट की सबसे बड़ी पी.एस.जी की मीटिंग में मैंने इस बात की शिकायत की थी कि किरंदुल से आकर पार्षद द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जो कि गलत है मेरी इस शिकायत को महाप्रबंधक ने गंभीरता से लेते हुए जल्द ही इस पर कारवाई करने की बात कही थी परंतु अभी पता चला है कि आज दिनांक तक भी वहां पार्षद कार्य कर रहा है इस विषय में दोबारा प्रबंधक से बात करूंगा।

जोगी कांग्रेस नहीं कर सकती बस्तर का भला : हरीश

जोगी कांग्रेस में जाना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल

जगदलपुर,(आरएनएस)। मैने सोचा था कि कांग्रेस में जिस तेवर और कलेवर से अजीत जोगी काम करते थे उससे मै खासा प्रभावित था। इसके चलते ही जब वे बस्तर के आदिवासी हित की बात को लेकर नई पार्टी बनाए तो मैने सोचा कि उनके साथ जुड़कर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलू। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जोगी सरकार जिस ढर्रे पर चल पड़ी है वो बस्तर का कभी भला नहीं कर सकती है। इस बात का एहसास मुझे समय रहते हो गया और मैने अपनी गलती को समझते दुबारा कांग्रेस में आने का फैसला किया। यह कहना है सुकमा के जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश का। उन्होंने कांग्रेस भवन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गोलमोल जवाब दिया कि जोगी कांग्रेस उन्हें अपने ही पिता के खिलाफ कोंटा विधानसभा में चुनावी मैदान में उतारने के फिराक में थी। इस बात की सगाई से वे इंकार करते रहे। कांग्रेस मेरी मातृ संस्था है। मैने अपने जीवन में यदि कोई भूल की तो जोगी कांग्रेस में जाकर। मेरी और मेरे परिवार की पहचान कांग्रेस से ही है। मेरे पिता अनपढ़ होकर भी कोंटा इलाके से चार बार के विधायक हैं। हालांकि वे अनपढ़ हैं लेकिन वे कांग्रेस के साथ रहकर सफल हैं और मैने आवेश में आकर जो कदम उठाया पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मै छह माह में ही फेल हो गया। यह कहना था कोंटा विधायक कवासी लखमा के पुत्र और सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरिश का जब वे कांग्रेस में लौटने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। हरिश का मानना है कि भाजपा जनता के साथ भेदभाव कर रही है। नक्सल मोर्चे के नाम पर आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है। पलायन के लिए लोग विवश हो रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से बंटी हुई थी और अजीत जोगी ने जनहित के लिए पार्टी बनाई थी उसे देखकर ऐसा लगता था कि जनता का भला होगा। समय के साथ पार्टी अपनी दिशा और दशा से भटक गई। इसके चलते ऐसा लगता है कि जोगी कांग्रेस से जनता का भला नहीं होगा। जनता का यदि कोई भला कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस है। यहीं कारण है कि मैने अपनी भूल को सुधारते कांग्रेस में वापसी की और अब जीवन पर्यन्त कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। हरीश ने उनसभी का आभार माना है जिन्होंने उन्हें कांग्रेस में वापस आने पर इतना सम्मान दिया है।

अचानक तय हुआ कार्यक्रम

कवासी हरिश से जब यह पूछा गया कि यूथ कांग्रेस के जिलाअध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी कांग्रेस भवन से नदारत हैं तो उन्होंने बताया कि कोंटा से वो अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए शहर आए थे। इस बीच उनकी चर्चा युवा साथियों से हुई। अचानक ही उन्होंने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। अब शहर आए हैं तो वे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलकर ही जाएंगे।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु General Knowledge

1 राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। अकबर द्वितीय

2 मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधी किसने प्रदान की। महात्मा गांधी

3 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। उत्तराखंड

4 महलों का शहर के नाम से कौनसा शहर जाना जाता है। कोलकाता

5 गंगासागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। चंबल मध्यप्रदेश

6 अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है। नेपानगर, मध्य प्रदेश

7 भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां पर खोला गया। टंकवार में 1716

8 किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति

9 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोक सभा

10 किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। वी.वी.गिरि

11 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 75

12 राज्य सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है। 30 वर्ष

13 वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है। 98

14 वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं। 62

15 वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। 52

16 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। सरदार बल्लभ भाई पटेल

17 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है। संविधान के 69वें संशोधन में

18 भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ब्रिटेन

19 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। आयरलैंड

20 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका

21 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका

22 भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्त्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं। जर्मनी

23 पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषण कब की गई। 26 जुलाई 1947

रमन कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला

0 सुत सारथी, सईस व सहीस वर्ग अनुसूचित जाति में शामिल
0-बैठक में 7 विधेयकों को भी दी आज मंजूरी
0-विनियोग विधेयक का अनुमोदन, पीएफ ब्याज दर पर भी फैसला

रायपुर,(आरएनएस)। रमन कैबिनेट की बैठक में आज पीएफ में ब्याज दर पर भी चर्चा हुई। बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि राज्य सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि में 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक ब्याज दर में 7.8 प्रतिशत रखा जाये..। दरअसल भारत सरकार ने इस अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि तथ और अन्य निधियों के अभिदाताओं को जमा रकम पर 7.8 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित रखा है। मंत्री परिषद की बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार सुत सारथी, सईस और सहीस जातियों को पिछड़ा वर्ग से हटाने का निर्णय लिया । दरअसल भारत सरकार ने इन जातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। वहीं आज कैबिनेट ने कई विधेयकों को भी हरी झंडी दी.. जो विधानसभा में पेश किये जायेंगे। जिन विधेयकों को मंजूरी दी गयी.. उनमें छत्तीसगढ़ निराश्रित व निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 संशोधन, छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक, जीएसटी लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन हेतु विधेयक, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन व सेवा शर्तो का विनियमन) विधेयक 2017, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश विधेयक, छत्तीसगढ़ श्रम विधियां और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन किया गया है।

अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी नहीं ये सर्टिफिकेट

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बर्थ सर्टिफिकेट के जरूरी सबूत माने जा सकते हैं। दरअसल सरकार लगातार भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने के प्रोसेस को आसान कर रही है। सरकार ने पार्लियामेंट को सूचित किया है कि आधार और पैन कार्ड दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पासपोर्ट नियमों 1980 के अनुसार 26/01/1989 के बाद पैदा हुए लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। लेकिन अब ये लोग मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड के आवेदक की जन्मतिथि सहित पिछले स्कूल में दाखिला/ स्कूल छोड़ने / मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट / पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड भी जाम कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अब अपना सर्विस रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। संसद में वी के सिंह ने कहा कि सरकार लगातार पासपोर्ट बनाने के प्रक्रिया को सरल कर रही है।

नायडू ने बेटा-बेटी को पहुंचाया करोडों का फायदा : जयराम

नइं दिल्ली,(आरएनएस)। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू पर अपनी बेटी और बेटे को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करने वाले नायडू को देश को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश ने यहां संसद भवन परिसर में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि हमेशा जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करने वाले नायडू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकार को चूना लगाया और बेटी तथा बेटे को पांच सौ करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। ईमानदारी, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लेकर उन्हें इन सवालों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। रमेश ने आरोप लगाया कि नायडू के प्रभाव में तेलंगाना सरकार ने गत 20 जून को एक विशेष आदेश जारी किया और स्वर्णभारत ट्रस्ट को सरकार को दो करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास शुल्क का भुगतान करने से छूट दे दी। इस ट्रस्ट में नायडू की बेटी प्रबंधन ट्रस्टी हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह से नायडू के बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार ने बिना निवदा निकाले दो कंपनियों को 270 करोड़ रुपए का आर्डर दिया। इन कंपनियों में एक के मालिक नायडू के बेटे हैं और दूसरी कंपनी के मालिक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भोपाल में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर छह अप्रैल 2011 को कुशाभाऊ ठाकरे स्मारक ट्रस्ट को दी गयी 20 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द किया गया था। यह जमीन भोपाल के अहम इलाके में थी और इसकी कीमत करीब छह सौ करोड़ रुपए थी। नायडू इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 1978 में नायडू जब आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधायक थे तो उन्होंने नगोर में भूमिहीनों की करीब पांच एकड़ जमीन अपने नाम करा ली थी लेकिन अगस्त 2002 में उन्हें यह जमीन प्रशासन को लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि नायडू को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए और देश की जनता को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

नागपंचमी पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 28 को

रायपुर,(आरएनएन)। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती क्रीड़ा समिति सरस्वती चौक पुरानी बस्ती द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जैतू सावमठ के पास 28 जुलाई को सुबह 10 बजे आयोजित की गई है। संस्था के सचिव रमेश यदु द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सीनियर वर्ग एवं जूनियर वर्ग में किया गया है।